

कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक सं.	65

दिनांक 10 अगस्त, 2018 को आयोजित 64 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक 10 अगस्त, 2018 को आयोजित 64 वीं त्रैमासिक SLBC बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं।
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

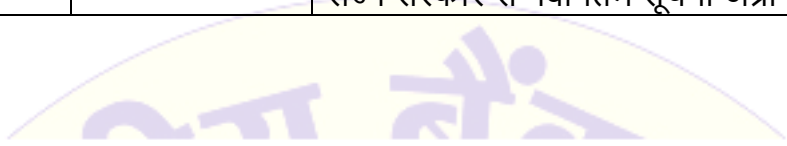
कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक सं.	65

पूर्व में आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	वर्तमान स्थिति
1	15.06.2018	Dedicated Certificate Officer नियुक्ति का मामला	Dedicated Certificate Officer एवं अन्य कर्मचारियों के कार्यालयीय खर्च की प्रतिपूर्ति बैंको द्वारा किये जाने के राज्य सरकार के सुझाव के अलोक में बैंको द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को पत्रांक SLBC/18-19/53 दिनांक 15.06.2018 के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, जिसमें बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि से 5% की राशि सरकारी कोष में जमा करने की सहमति दी गयी थी। पिछली SLBC की बैठक के दौरान इस पर राज्य सरकार द्वारा एक बैठक किये जाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई बैठक नहीं हो पाई है और यह मामला अभी तक विचाराधीन है।
2	23.07.2018	बैंको को सरकारी भूमि का आवंटन का मामला	राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में SLBC एवं अन्य बैंको को आवंटित किये जाने वाली भूमि के क्रय मूल्य में किये गए परिवर्तन पर विस्तृत चर्चा हेतु विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई बैठक नहीं हो पाई है।
3	27.11.2017	SARFAESI के अंतर्गत physical possession के लिए लंबित cases	कई बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 27.11.2017 को जिलावार pending cases की जानकारी राज्य सरकार को दी गयी थी। उनमें से अधिकतर मामले अभी भी जिले में लंबित हैं।
4	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराया जाना है, जिसपर सरकार की ओर से इसे राज्य में जल्द लागू कराये जाने का आश्वासन दिया गया था। नवीनतम सूचना अप्राप्त।
5		बिना LPC के KCC ऋण देने की वर्तमान सीमा रु 1.00 लाख से अधिक करना	राज्य में कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ाये जाने की दिशा में यूनिजन बैंक द्वारा पिछली SLBC की बैठक के दौरान बिना LPC के KCC ऋण देने की वर्तमान सीमा रु 1.00 लाख से बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया था, जिसपर कृषि निदेशक द्वारा विभाग से विचार कर इस पर जल्द ही कोई निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया था।

6		land records को अद्यतन किया जाना	PNB द्वारा राज्य में land records को अद्यतन (dizitization) किये जाने के बावजूद इसके regular updation नहीं किये जाने के कारण वास्तविक जमीन मालिक के सही पहचान में आ रही कठिनाई का मामला उठाया गया।
7		SUI	DFS द्वारा राज्य सरकार से इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के margin money को arrange करने के लिए किसी तरह का प्रावधान करने की बात कही गयी। राज्य सरकार से नवीनतम सूचना अप्राप्त।



बैंक से संबंधित मामले

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ सं-3 (a) से 3 (d) पर संलग्न है।

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	07.12.2018
बैठक सं.	65

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	30.09.2017	30.06.2018	30.09.2018	Bench Mark
1	Deposit	189992.80	198214.28	207019.21	
	CASA Deposit	87204.03	90731.75	92942.85	
2	Credit	81599.81	86863.17	91399.54	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	30084.34	30782.35	31373.73	
4	Total Credit	111684.15	117645.52	122773.27	
5	CD Ratio	58.78	59.35	59.31	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	42282.95	45573.29	48489.84	
7	Share of PSA to Total Advances (%)	51.82%	52.47%	53.05%	40
8	Agricultural Advances	12860.28	13510.82	13723.45	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	15.76%	15.55%	15.01%	18
10	i. Micro & Small Enterprises Advance	19582.90	20323.37	21823.55	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	24.00%	23.44%	23.87%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	58.18%	59.90%	57.35%	
11	Advances to Weaker Sections	14308.20	14937.72	15169.46	
12	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	17.53%	17.19%	16.60%	10
13	DRI Advances	36.72	31.15	30.88	
14	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.05%	0.04%	0.03%	1
15	Advances to Women	10309.18	11455.11	10427.00	
16	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	12.63%	13.19%	11.41%	5
17	Advances to Minorities (Amount)	5454.27	5806.86	5857.91	
18	Share of Advances to Minorities under PSA (%)	12.90%	12.74%	12.08%	15
19	Gross N.P.A	4929.06	5099.35	5275.93	
	Provision	2291.40	2571.05	2633.41	
	Net NPA	2637.66	2528.30	2642.52	
	Gross NPA Percentage	6.04%	5.87%	5.77%	
	Net NPA Percentage	3.23%	2.91%	2.89%	
20	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1497	1498	1473	
	Semi-Urban	780	785	753	
	Urban	726	729	789	
	Total	3003	3012	3015	
21	ATM installed in Jharkhand	3507	3471	3497	

*Annexure- V,

As per Annexure - I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV, Annexure -XIX

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 30 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक रूपये 17026.41 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है। वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 8.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में यानि 30 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक रूपये 9799.73 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 12.00 प्रतिशत दर्ज की गई है।

ऋण – जमा अनुपात (C.D Ratio)

यद्यपि 30.09.2017 की तुलना में 30.09.2018 में CD ratio में वृद्धि दर्ज की गई है, परन्तु पिछली तिमाही से बैंकों का सीडी अनुपात (RIDF एवं Place of Utilization को सम्मिलित करते हुए) पुनः आंशिक रूप से कम होकर सितम्बर 2018 में 59.31 % रह गया है, जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 60% से कुछ कम है। यद्यपि बैंकों के core CD ratio में पिछले तिमाही 43.82 की तुलना में वृद्धि हुई है और यह बढ़कर सितम्बर 2018 में 44.15 हो गया है। सभी बैंकों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.68% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 53.05 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

30 जून 2018 को कृषि अग्रिम रू. 13510.82 करोड़ था जो कुल अग्रिम का 15.55 प्रतिशत था। यद्यपि पिछली छमाही में कृषि ऋण के अंतर्गत कुल रू. 2026.60 करोड़ संवितरित किये गए हैं, परंतु वर्तमान में कृषि ऋण कुल रु 13723.45 करोड़ है, जो कुल अग्रिम का 15.01 % है, जो कि राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% से कम होने के कारण एक चिंतनीय प्रश्न है और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है। लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतु अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंकों को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा।

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

30 सितम्बर 2018 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 15169.46 करोड़ (16.60 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

30 सितम्बर 2018 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रू. 10427.00 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 11.41 % है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है।

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

30 सितम्बर 2018 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रू 5857.91 करोड़ है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 12.08 % है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है। इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

30 सितम्बर 2018 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15, दिनांक 01.07.14 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)		
DETAILS	30 th September, 2017	30 th September, 2018
Aggregate Deposits	189992.80	207019.21
CORE ADVANCES	81599.81	91399.54
Place of Utilization	25162.78	25915.51
RIDF	4921.56	5458.22
NET ADVANCES	111684.15	122773.27
CD Ratio	58.78	59.31

(परिशिष्ट- 4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

	Deposit (Rs in Crores)	Advances (Rs in Crores)
Small Finance Banks	106.44	455.05

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या- 6 (a)}

हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि सितम्बर 2018 में बैंको के समग्र ऋण में वृद्धि हुई है और हमारा core CD Ratio पिछली तिमाही के दौरान 43.82% से बढ़कर 44.15% हो गया है। राज्य में कार्यरत 03 small finance banks, Jana, Ujjivan और Utkarsh के deposit और advance को सम्मिलित करने के पश्चात् राज्य का CD Ratio 59.50 होता है जो कि राष्ट्रीय मानक से 0.50 कम है। इस दिशा में समुचित प्रयास की आवश्यकता है।

Incremental CD Ratio से सम्बंधित बैंकवार /जिलावार रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-6(b) एवं 6(c) पर दर्शायी गयी है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक संख्या	65

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के तहत उपलब्धियों की समीक्षा : 30 सितम्बर 2018 तक

30 सितम्बर 2018 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रु करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2017-18)	ACHIEVEMENT IN AFY 2017-18		ANNUAL TARGET (2018-19)	ACHIEVEMENT IN AFY 2018-19	
	AMT.	AMT	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	7682.37	3757.56	48.91	8336.60	2026.60	24.31
MSME	7329.51	10337.95	141.05	8560.35	4518.70	52.79
OPS	3821.41	2132.47	55.80	4213.60	1184.29	28.10
Total Priority	18833.29	16227.98	86.16	21110.55	7729.59	36.61
Non Priority	8582.15	8605.03	100.26	8773.34	7143.91	81.43
Total	27415.45	24833.01	90.58	29883.89	14873.49	49.79

कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न बैंको एवं जिलों द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को क्रमशः पृष्ठ सं-7(a) एवं 7 (b) में दर्शाया गया है।

टिप्पणियां :

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम छमाही के दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 49.79 % समग्र ऋण का संवितरण हुआ है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में हुई 47.48 % संवितरण की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
- कृषि क्षेत्र में कुल वार्षिक योजना के विरुद्ध केवल 24.31 % ऋण का संवितरण ही हो पाया है। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। बैंको एवं जिलों के कृषि क्षेत्र में हुई उपलब्धि को पृष्ठ संख्या- 7 (c) एवं 7 (d) पर दर्शाया गया है और प्रति शाखा किये गए उपलब्धि के आधार पर उनके प्रदर्शन को क्रमबद्ध किया गया है।
- MSME sector में इस वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा MSME के वार्षिक बजट के विरुद्ध 52.79% की उपलब्धि सराहनीय है।
- 2018-19 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-6 में दर्शाया गया है एवं Agriculture Term Loan में बैंकवार एवं जिलावार segment wise संवितरण और o/s का रिपोर्ट annexure-7 में दिया गया है।

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक संख्या	65

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार रू. 13723.45 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.01 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुनः बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	Disbursement during 2018-19		Outstanding In KCC A/Cs As of 30.09.2018	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	194599	696.63	1257382	4774.31
Pvt. Banks	21464	86.09	39254	197.27
Total	216063	782.72	1296636	4971.58
RRB	75515	258.85	368580	1491.01
Co-op Banks	746	1.89	19432	32.78
Total	292324	1043.46	1684648	6495.37

(KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है)

- ❖ सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। दिनांक 30.09.2018 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार कुल 1513791 eligible KCC खातों में से 1337540 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1310569 खातों में (98%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।
(विवरण पृष्ठ सं-8(a) एवं 8(b) में संलग्न है)
- ❖ प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या- 8 (c) एवं 8 (d) पर दर्शाया गया है।

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

(Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular		Outstanding position as at the end of		
			Sept 2017	Sept 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	
MICRO & SMALL ENTERPRISES					
1	Micro Enterprises		Accounts	1832	600
			Amount	11394.39	12516.69
2	Small Enterprises		Accounts	45	49
			Amount	8188.51	9306.86
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)		Accounts	1877	649
			Amount	19582.90	21823.55
MEDIUM ENTERPRISES					
4.	Total of Medium Enterprises		Accounts	06	08
			Amount	1419.47	2412.31
MSME					
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			Accounts	1884	657
			Amount	21002.38	24235.86
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	55.69%	57.35%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	23.99%	23.87%

(MSME रिपोर्ट –annexure-9)

COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE) (Position as on 30.09.2018)

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		TOTAL	
A/C	Amt	A/C	Amt.
363	17380.07	125	4634.20

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 9 a में संलग्न है)

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध सितम्बर, 2018 में 57.35 % है।
- बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य में, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 3.63 लाख (लगभग) MSE ऋण खातों हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं । इनमें से 1.25 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 34.43 % खातों में CGTMSE कवरेज लिया गया है । इस सम्बन्ध में सभी बैंको से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE coverage लेने का प्रयास किया जाये । SLBC द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अवर सचिव से प्राप्त पत्र 403 दिनांक 31.10.2018 को सभी बैंको को प्रेषित किया गया है जिसमें भारत सरकार के सूक्ष्म,

लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के पत्र का हवाला देते हुए सभी बैंको से इस scheme के तहत MSE sector में ज्यादा credit दिए जाने का निर्देश दिया गया है।

5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी। परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, dairy, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है। PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है।

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.18 से 30.09.18 तक) (राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	No.	AMT	No.	AMT.	No.	AMT.	No.	AMT.
Sanctioned	41127	117.51	24454	568.74	5655	443.19	71236	1129.44
Disbursed	40612	109.32	24290	504.38	5616	402.26	70518	1015.96

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में Micro Finance Institutions के द्वारा लगभग 548702 खातों में रु 1452.51 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और रु 1337.60 करोड़ की राशि वितरित की गई है। इस तरह MUDRA योजना के तहत राज्य में अब तक कुल 619220 खातों में रु 2353.56 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ है।

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10 (a) एवं 10(b) में सलग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 30.09.2018 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	Male Beneficiaries	Out of total Beneficiaries, SC/ST Beneficiaries	Loan Sanctioned Amt (Rs in Cr)
100	93	07	11	24.25

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10(c) में सलग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 30.09.17	As on 30.09.18				Total As on 30.09.18	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSE MENT DURING FY 2018-19
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	62787	66386	598	798	81	67863	679.64	6241
Amount (In crore)	2579.47	3212.11	21.77	24.62	0.61	3259.11		335.38

(Annexure-10)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही तक शिक्षा ऋण के तहत कुल 6241 खातों में 335.38 करोड़ रु की राशि के संवितरण की रिपोर्टिंग की गई है।
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति (annexure -10 A) इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में)	संख्या	राशि (रु करोड़ में)
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2018-19)			6241	335.38
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण	2756	130.55	2547	63.83
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	624	28.08	618	13.60

5.4 आवास ऋण

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु. करोड़ में)

Particulars	Up to 30.09.17	30.09.2018				Total Up to 30.09.18	Growth in H/Loan Y-on-Y	Disburse ment in AFY 18-19
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	69552	73121	5628	903	0	79652	698.17	7569
राशि	6880.74	8137.84	656.25	41.92	0	8836.01		1080.13

(रिपोर्ट –annexure-11)

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

30 सितम्बर, 2018 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु.करोड़ में)

30 सितम्बर, 2017		% Share	30 सितम्बर, 2018		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
42282.95	5454.27	12.90%	48489.84	5857.91	12.08%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 सितम्बर, 2018 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु.करोड़ में)

30 सितम्बर, 2017		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	30 सितम्बर, 2018		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
81599.81	10309.18	12.63%	91399.54	10427.00	11.41%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

30 सितम्बर, 2018 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

30 सितम्बर, 2017		DRI Percentage in Net Credit	30 सितम्बर, 2018		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI		Net Credit	DRI	
81599.81	36.72	0.05%	91399.54	30.88	0.03%

(रिपोर्ट –annexure-12)

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रु. करोड़ में.)

30 सितम्बर, 2017		% achievement	30 सितम्बर, 2018		% achievement
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
81599.81	12560.85	15.39%	91399.54	11429.93	12.51%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 237163 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 123472 खातों का credit linkage है, जिसमें कुल रु 978.58 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रु 695.22 करोड़ है।

(रिपोर्ट- Annexure-15)

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (30 सितम्बर, 2018 तक) Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March'18	Addition during AFY-18-19	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	200	41	241
No of Villages	15733	2572	18305
Total No of SHGs supported by SRLM	132531	28588	161119
Total families supported by SRLM	1597905	344554	1942459
No of SHG receiving R.F	55741	12952	68693
Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs)	8361	1942.80	10303.80
No of SHG receiving CIF	33901	2484	36385
Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs)	18783	1242	20025
No. of SHG credit linked with Banks	66166	5632	71798
Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs)	49005.45	5632	54637.45

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम छमाही के दौरान बैंको द्वारा SLBC के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 5497 SHGs को credit लिंक किया गया है, जबकि JSLPS के द्वारा इस अवधि में credit linked किये गए SHGs की संख्या 5632 बताई गई है।

(JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-13 (a) एवं 13 (b) में दिया गया है।)

बैठक की तिथि	07.12.2018
बैठक की संख्या	65

**वित्तीय समावेशन एवं
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3720	458	Nil	3595	5140

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (a) & 14 (b)}

B Online transaction करने वाले BC की स्थिति

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
6096	5321	3145	951	1225

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (c)}

C. PMJDY के तहत 30.06.2018 तक खोले गए खातों की स्थिति

30.09.2018 तक खोले गए खातों की संख्या			PMJDY खातों में जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
8438381	3262987	11701368	8468264	10639723	8371324	6984822	5545234

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (d) & 14 (e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

यद्यपि पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 8468264 रूपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रूपे कार्ड में से केवल 6984822 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमें से भी अब तक केवल 5545234 खातों में रूपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रूपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरूरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबंधित बैंकों से प्राप्त आंकड़ा पृष्ठ संख्या-15 (a) में दर्शाया गया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना” के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागू किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक: 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-

PMJJBY	PMSBY	APY	
Total Enrolment	Total Enrolment	Enrolment during 18-19	Total Enrolment since inception
636468	2988603	40697	267426

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-15 (b) सलग्न है)

वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गाँवों में बैंकिंग शाखा खोलने संबंधित रोडमैप

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था। झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिह्नित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमें से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है, बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था।

आरबीआई के नये दिशा निर्देश के अनुसार सप्ताह में **कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे** एक नियत स्थल पर कार्य कर रहे BC को **बैंकिंग आउटलेट**, माना जा सकता है। इस निर्देश के अनुसार निर्धारित सभी 137 गाँव में बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके हैं।

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक सं	65

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबंधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दिनांक 30 सितम्बर 2018 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

[राशि करोड़ में]

विवरण	30.09.2017	30.06.2018	30.09.2018	Variation over last FY
Advances	81599.81	86863.17	91399.54	9799.73
Gross NPA	4929.06	5099.35	5275.93	346.87
Provision	2291.40	2571.05	2633.41	342.01
Net N.P.A	2637.66	2528.30	2642.52	4.86
Percentage of Gross NPA	6.04%	5.87%	5.77%	(-)0.27%
percentage of Net NPA	3.23%	2.91%	2.89%	(-)0.34%

(रिपोर्ट- annexure-19)

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A), एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। रु 5275.93 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 5.77 % है, एक चिंताजनक आंकड़ा है।

(विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलग्रक के रूप में दर्शाये गए हैं।)

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 30 सितम्बर 2018 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qtr.		Cases dispoed during last Qtr.		status as on 30.06.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
121675	215.33	9286	52.05	2955	51.37	128006	216.01

(रिपोर्ट- annexure-20)

DRT केस की स्थिति

दिनांक 30 सितम्बर 2018 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 30.06.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
2175	758.84	68	43.62	208	60.74	2035	741.72

(रिपोर्ट- annexure-21)

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार, SARFAESI cases की position निम्नवत है:

(Rs in Cr)

Notices Issued U/S 13 (2) of SARFAESI Act		Out of which symbolic possession taken under 13(4)		Request sent to Dist Authority for assistance in Physical Possession	Physical Possession taken	No. of cases pending at dist. level
A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	A/C	A/C
4671	1845.86	1815	837.13	625	56	569

(रिपोर्ट- annexure-22)

NB: SLBC द्वारा विभिन्न बैंको से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर PMEGP, KCC तथा PMMY योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋण में NPA की स्थिति के आकलन का प्रयास किया गया है। यद्यपि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ों में विसंगतिया है, परन्तु इन आंकड़ों के अध्ययन से NPA की बढ़ती समस्या का पता चलता है। {रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-17 (a) एवं 17 (b)}

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक सं	65

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-टैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने वेबसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक **31.10.2018** तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved
6238	165.78	350	9.02	1669	44.99	4255	111.46

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.10.2018 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है)

8.2 NULM & PMAY

शहरी विकास विभाग से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-18 (a) एवं 18 (b) में एवं शहरी विकास विभाग और बैंकों से प्राप्त PMAY से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-18 (c) में दर्शायी गई है।

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	07.12.2018
बैठक संख्या	65

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of **30.09.2018**)
झारखण्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित)		1 जिला

AFY 18-19 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -573 ; प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17110

उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -267 प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 7619

{ विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-19 (a)}

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन - 07

भवन निर्माण कार्य लगभग सम्पूर्ण/finishing work जारी - 05

भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 12

भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी - 01

(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-19 (b) से 19 (d) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2017-18 के दौरान		AFY 2018-19 के दौरान	
कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked
17660	2461	7619	641

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-19 (e) एवं 19 (f) पर उपलब्ध है)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर)	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	15
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू	7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 15 केन्द्र ; **वनांचल ग्रामीण बैंक** - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है ।

जुलाई -सितम्बर 2018 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	1056
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	3181
कुल	4237

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-20 (a) एवं 20 (b) पर उपलब्ध है}

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	07.12.2018
बैठक संख्या	65

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज
पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:
एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1) प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2) प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2) नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	26.11.2018
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4) उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक 6) अन्य सदस्य बैंक, स्टेट	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2) हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम	प्रस्तावित तिथि 04.12.2018

			बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	कारकों का प्रोत्साहन	
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक- एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	11.01.2018
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप- समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9)यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	प्रस्तावित तिथि 04.12.2018
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक -	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड	1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें	12.11.2018

		एसएलबीसी	4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)	
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	02.02.2015
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	20.08..2018 को RBI Empowered Committee on MSME की 39 वीं बैठक बुलायी गई थी।
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दे (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	07.11.2017
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	20.11.2018

10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	20.11.2018
11	NPA पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, संस्थागत वित्त 2) एसएलबीसी 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 9) केनरा बैंक 10) UCO Bank	राज्य में NPA एवं recovery की स्थिति; DRT, Certificate एवं SARFAESI cases	प्रस्तावित तिथि 04.12.2018

कार्यसूची सं.	11
बैठक की तिथि	07.12.2018
बैठक सं.	65

विविध कार्यसूची

1. लगभग 1 वर्ष से ऊपर बीत जाने एवं बार –बार लिखित एवं मौखिक आग्रह किये जाने के बावजूद IOB ने रांची के मोरहाबादी मैदान में दिनांक 12.10.2017 को आयोजित “मुद्रा प्रोत्साहन अभियान” कार्यक्रम पर हुए व्यय के लिए अब तक अपना contribution SLBC को प्रेषित नहीं किया है। इस forum के माध्यम से हम IOB के नियंत्रक प्रमुख से आग्रह करते हैं कि यह राशि SLBC को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाये।

(Action: IOB)

2. Urban Development & Housing Finance, GoJ के पत्रांक 2295 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा DAY-NULM scheme के SEP Component के लिए तैयार किये गए centralised bank code और product code को सभी बैंको के साथ share किया गया था और बैंकों से अपने database में आवश्यक updation करने का निर्देश दिया गया था। संभवतः सभी बैंको द्वारा यह सुधार कर लिया गया होगा। सभी बैंको से आग्रह है कि इसकी अद्यतन सूचना से Urban Development & Housing Finance, GoJ को अवगत करा दें।

(Action: सभी सम्बंधित बैंक)

3. DFS द्वारा सभी aspirational एवं LWE जिलों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 31.10.2018 तक झारखण्ड में 5 KM के दायरे में चिन्हित 440 स्थानों पर BC की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, जिसमे से केवल 11 स्थानों (जामतारा, गढ़वा और लातेहार जिला) पर ही BC की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है और शेष सभी स्थानों पर ये कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(Action: VGB, SBI एवं संबंधित LDMs)

4. DFS के पत्रांक 20/57/2010-FI दिनांक 22.11.2017 के द्वारा LWE जिलों में banking services के expansion के लिए झारखण्ड राज्य के पलामू में 06 स्थानों को चिन्हित कर बैंक की शाखाएँ खोले जाने का प्रस्ताव था। इन 06 स्थानों पर PNB, Union Bank of India, Andhra Bank एवं SBI द्वारा दिनांक 31.10.2018 तक शाखा खोला जाना था। PNB द्वारा Naudiha Bazar एवं Pipra में तथा Andhra Bank द्वारा Lalgahar Bihar में बैंक शाखा खोल दिया गया है। SBI एवं Union Bank द्वारा शेष 03 स्थानों Untari Road, Ramgarh एवं Pandu में शाखा खोलने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है।

(Action: LDM Palamu, Union Bank एवं SBI)

5. DFS द्वारा राज्य में कार्यरत सभी बैंको को दिनांक 30.11.2018 तक कुल 3.24 लाख नए PMJDY खातों को खोलने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध दिनांक 25.11.2018 तक लगभग 2.23 लाख खाते खोले जा चुके हैं। सभी बैंको से निवेदन है कि लक्ष्य के विरुद्ध हुई उपलब्धि से सम्बंधित आंकड़े SLBC को नियमित रूप से प्रेषित करते रहें ताकि इसकी reporting DFS को की जा सके।

(Action: सभी बैंक)

6. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 59 minutes में रु 1.00 करोड़ तक के MSME लोन को पोर्टल पर online principal स्वीकृति देने की योजना में झारखण्ड राज्य के कुल चार जिलों, बोकारो, जमशेदपुर, गोड्डा और खूंटी की reporting संबंधित LDMs के द्वारा दिनांक 02.10.2018 से अगले 100 दिनों तक की जानी है। इसके तहत चिन्हित जिलों में जिला अग्रणी प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक सप्ताह के 02 दिनों मंगलवार एवं शुक्रवार को MSME entrepreneurs के लिए जिला प्रशासन की सहायता से camp आयोजित किया जाना है और उस जिले के लिए identified activity के अलावा भी अन्य MSME activities के लिए आवेदन सृजित कर 59 minutes के online portal पर स्वीकृति दी जानी है। सभी बैंको एवं संबंधित LDMs से आग्रह है कि इसकी reporting उचित फोरम पर करते रहें और इसकी जानकारी SLBC को भी देते रहें। इसके साथ ही हम ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.11.2018 को दिए गए दिशा निर्देशों का भी उल्लेख करना चाहेंगे जिसके तहत MSME Entrepreneurs के लिए आयोजित किये जाने वाले camps में RSETI से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को बैंको से credit linkage कराने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया है।

(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं

LDM)

7. पिछली SLBC की SHG पर बनी sub committee की बैठक में प्रत्येक माह में एक दिन Community Based Recovery Mechanism की meeting का प्रस्ताव approve किया गया था। इसके लिए माह के दुसरे सप्ताह में बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है। JSLPS के पत्रांक 1771 दिनांक 12.11.2018 एवं SLBC के द्वारा भी सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से अपनी शाखाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

(Action: सभी

बैंक)

8. RBI के revamp Lead Bank Scheme के अनुसार SLBC द्वारा सभी LDMs को SLBC portal पर direct access दिया जाना प्रस्तावित है ताकि LDMs अपने जिलों से सम्बंधित data प्राप्त कर सकें। हालाँकि इससे पूर्व सभी बैंको को अपने MIS system में आवश्यक सुधार कर प्रखण्ड वार एवं जिलावार data देने का प्रावधान किया जाना है जिसे SLBC के portal पर सीधे upload किया जा सके। चूँकि यह प्रक्रिया अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाई है अतः SLBC के portal पर LDMs को direct access न देकर SLBC द्वारा सभी LDMs को उनके जिलों से सम्बंधित आंकड़े इस quarter से हम उपलब्ध करा रहे हैं और सभी LDMs से यह आग्रह है कि वे अपने जिलों में DCC/DLRC की बैठकों में इन्हीं आंकड़ों के आधार पर चर्चा करें। साथ ही हम RBI से भी यह निवेदन करते हैं कि SLBC की त्रैमासिक बैठक के तिथि के बाद ही जिलों में DCC/DLRC की बैठकों के लिए तिथिय निर्धारित की जाएँ। इस क्रम में बैंको के आंकड़ों में भी अपेक्षित सुधार संभव हो पायेगा। RBI से हम साथ ही ADEPT system (Automated Data Extraction Project) पर हो रहे प्रगति की जानकारी दिए जाने का भी आग्रह करते हैं।

(Action: सभी बैंक, सभी LDMs एवं

RBI)

9. वर्तमान में 100 smart cities, जिसमे रांची भी शामिल है, में digital payments के लिए merchants को onboard किये जाने के लिए DFS द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। रांची के साथ साथ सभी LDMs एवं सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से हमारा आग्रह है कि वे इस दिशा में समुचित ध्यान दें।

(Action: सभी LDMs एवं

सभी बैंक)

10. हमारे राज्य में SUB SERVICE AREA (4175) को विभिन्न बैंको को आवंटित/चिन्हित करने का कार्य काफी काफी समय पूर्व हुआ है। इस बीच कई जिलों में नए ब्लॉक/प्रखण्ड का सृजन किया गया है। कई जिलों में उन प्रखंडों में SUB SERVICE AREA UPDATION का कार्य नहीं हुआ है। सितंबर महीने में एसएलबीसी द्वारा सभी एलडीएम से इस संबंध में सूची ली गई थी। कई जिलों की सूची

अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण थी। इसके स्पष्ट निर्धारण के अभाव में इन इलाकों में बैंको द्वारा BC की नियुक्ति एवं अन्य योजनाओं के संचालन में कठिनाई आ रही है। इस कारण संबंधित विषय पर एक नए सिरे से कार्य करने की जरूरत है। सभी एलडीएम से आग्रह है कि दिसम्बर माह के अंत तक BLBC मीटिंग कर ज़िले के सभी गाँव को उनके नजदीकी बैंक की शाखाओं को आवंटित कर दें और नव आवंटन की सूची एसएलबीसी को प्रेषित कर दें ताकि इसे सभी बैंको को उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही एसएलबीसी के वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित किया जा सके। LDMs से अनुरोध है कि सभी गांवों को विभिन्न बैंको को आवंटित किये जाने का कार्य काफी सावधानीपूर्वक किया जाये और इसे BLBC की बैठक में अनुमोदित करा लिया जाये ताकि इस पर भविष्य में कोई असंतोष न हो।

(Action: सभी LDMs एवं सभी बैंक)

कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	07.12.2018
बैठक सं	65

Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वान पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमें Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है। इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है। राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 30.09.2018 तक राज्य में कुल 33554 POS machines का installation कराया जा चुका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था। यद्यपि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 4.05 लाख credit card, 2.12 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 23.78 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है।

{प्रगति प्रतिवेदन सलग्न-पृष्ठ सं-27 (a)}



कार्यसूची सं.	13
बैठक की तिथि	07.12.2018
बैठक सं	65

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

64th SLBC की बैठक में हुए कार्यवाही/निर्णय के आधार पर चिन्हित मुख्य बिंदु और उनपर कृत कार्यवाही

क्रम संख्या	कार्यवाही बिंदु	निष्कर्ष	कृत कार्यवाही
1	Incremental CD ratio	RBI द्वारा SLBC से राज्य में प्रत्येक तिमाही के अंत में दर्शाए जाने वाले CD Ratio के साथ साथ प्रत्येक तिमाही के दौरान incremental CD ratio (Bankwise/Districtwise) की जानकारी दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया	Bankwise/Districtwise incremental CD ratio की जानकारी agenda book में सम्मिलित की गयी है।
2	Small Finance Bank	राज्य में कार्यरत small finance banks के उपलब्धियों को भी प्रगति प्रतिवेदन में शामिल करने एवं उनके लिए SLBC द्वारा target निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया गया	राज्य में कार्यरत तीनों small finance banks के प्रगति प्रतिवेदन को शामिल किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से इन बैंको को वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर target दिए जाने का प्रस्ताव है।
3	ACP	Agr Sub Committee की बैठक कर राज्य के लिए निर्धारित किये गए ACP के साथ सभी बैंको के business target को synchronize करना	दिनांक 28.09.2018 को agr sub committee की हुई बैठक में NABARD एवं सभी बैंको से यह आग्रह किया गया है कि PLP बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये। NABARD के द्वारा सभी DDMs को इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाये कि वे प्रखंड स्तर पर सभी बैंको के साथ PLP बनाने से पूर्व एक meeting अवश्य कर लें।
4	Correct एवं Timely data का submission	सभी बैंको से SLBC को correct एवं timely data दिए जाने का निर्देश दिया गया और SLBC से ऐसा न करने वाले बैंकों के लिए agenda book में अलग से comment किये जाने की बात कही गयी	लगभग सभी बैंकों द्वारा इस बार timely रिपोर्ट submit किया गया है।
5	बैंक की शाखा खोलना/सभी uncovered centres पर BC की नियुक्ति/BC के deployment को rationalize किया जाना	बैंको से राज्य में identified सभी locations पर निर्धारित समयावधि के अंदर बैंक की शाखाएं खोलने तथा BC नियुक्त किये जाने का आग्रह किया गया। सखी मंडल की महिलाओं को मुख्य रूप से BC के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सभी बैंको एवं LDMs को BC के deployment को rationalize किये जाने की बात कही गयी ताकि सभी क्षेत्रों को BC से कवर किया जा सके।	इस दिशा में सभी बैंकों एवं SLBC द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस स्थिति में काफी सुधार भी हुआ है।
6	SLBC की बैठक के लिए agenda items का निर्धारण	SLBC की मीटिंग के लिए agenda items को चिन्हित करने का सुझाव दिया गया और सरकार से सम्बंधित मुद्दों को meeting से यथासंभव पहले सम्बंधित विभागों को उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही DCC/DLRC की बैठक में लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों को SLBC के agenda में लाये जाने की बात कही गयी।	SLBC की steering sub committee की दिनांक 12.11.2018 को हुई बैठक में RBI के दिशा निर्देशों के मद्देनजर सभी major banks के सहयोग से agenda items को finalise करने का प्रयास किया गया है।
7	SHG reporting	SHG sector के reporting में स्वीकृत राशि एवं वर्तमान बकाया शेष के साथ साथ वितरित की गयी राशि का भी उल्लेख करने का निर्देश दिया गया	इस बार से SLBC के agenda book में disbursement की राशि दर्शायी जा रही है।

8	SLBC meeting में विशेष आमंत्रण	SLBC की meeting में special guests/academicians, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त किये गए लाभार्थियों अथवा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े अन्य लाभार्थियों को बुलाया जाने का प्रावधान	इस दिशा निर्देश के आलोक में इस बार SLBC के द्वारा BC के रूप में नियुक्त किये गए SHG की महिलाओं को अपने अनुभवों को साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया है।
9	बैंको के performance के आधार पर ranking किया जाना	SLBC द्वारा विभिन्न बैंको/शाखाओं/बैंक मित्रों के द्वारा किये गए उपलब्धि के आधार पर उनकी ranking निर्धारित करना और साथ ही non-performing बैंको/ अधिकारियों/ अग्रणी जिला प्रबंधकों की जानकारी दिया जाना	कुछ महत्वपूर्ण parameters के मापदंड पर SLBC में प्रेषित आंकड़ों के आधार पर ranking तैयार की गई है।
10	CD Ratio	40% से कम CD ratio वाले बैंको/जिलों में Monitorable Action Plan के आधार पर किये जाने वाली कार्यवाहियों से सरकार को अवगत कराना	बार बार आग्रह के बावजूद किसी भी बैंक और LDM के द्वारा MAP की जानकारी SLBC को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
11	RSETI/कौशल विकास/ग्राम विकास समिति	RSETI के निर्माणाधीन भवनों को निश्चित समय सीमा तय कर पूर्ण किये जाने, बैंको द्वारा कौशल विकास केन्द्रों के साथ coordination किये जाने एवं ग्राम/आदिवासी विकास समितियों का खाता खोले जाने के सम्बन्ध में	RSETI के निर्माणाधीन भवनों की अद्यतन जानकारी book में दी गयी है। अन्य मुद्दों से सम्बंधित जानकारी SLBC को नहीं दी गयी है।
12	SLBC की बैठक में किसी एक मुद्दे को प्रमुखता दिया जाना	SLBC की प्रत्येक बैठक में किसी एक agenda item पर focus करने की सलाह दी गयी ताकि उसका त्वरित और उचित समाधान निकला जा सके	पिछली SLBC की बैठक के दौरान ही विकास आयुक्त द्वारा इस SLBC के लिए कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दिए जाने का निर्देश दिया गया था, जिसकी जानकारी सभी हितधारकों को ATR एवं minutes के माध्यम से दे दी गयी थी। इस दिशा में अपेक्षित परिणाम अभी भी परिलक्षित नहीं हो पा रहा है।
13	सरकारी योजनाओं के पैसे का ऋण खाते में समायोजन	विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत DBT के माध्यम से दिए जा रहे सहायता राशि का लंबित ऋण खातों में समायोजन कर लिए जाने के मुद्दे पर कोई व्यवस्था बनायी जाये	DFS एवं RBI के संयुक्त प्रयास से ऐसी व्यवस्था बनाये जाने की बात कही गयी थी परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में हुई किसी भी प्रगति की जानकारी SLBC के पास नहीं है।
14	KYC	ग्राहकों से KYC documents बार बार एवं अनावश्यक रूप से नहीं माँगा जाना चाहिए	DFS द्वारा पिछली बैठक में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बैंको द्वारा KYC के लिए नियत प्रावधानों के तहत की गयी कार्यवाही को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है परंतु नियत प्रावधानों से इतर किसी भी तरह से ग्राहकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सभी बैंको को इस सम्बन्ध में RBI के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सूचना दे दी गयी है।
15	PMJDY/BSBD a/cs में सरकारी राशि की जमा/निकासी	जन धन खातों अथवा BSBD a/cs में सरकारी राशि के जमा/निकासी पर बैंको द्वारा लगायी जानेवाली पाबन्दी पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है	सभी बैंकों को निर्धारित नियमों का पालन किये जाने के लिए प्रत्येक उपयुक्त फोरम से बारंबार हिदायत दी जा रही है।
16	APY	PMSBY एवं PMJJBY के साथ साथ APY में भी ज्यादा से ज्यादा subscribers को enrol किये जाने का निर्देश दिया गया	लगभग बैंको एवं LDMs के साथ होने वाली सभी बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ share किया जाता है और इसमें प्रगति भी हो रही है।

17	पंचायत भवन मुख्यालयों में ATM की व्यवस्था	हर जिले में ATM की आवश्यकता वाले पंचायतों/स्थानों का अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंको के द्वारा चयन IG, Operations श्री आशीष बत्रा ने 250 वैसे centres की जानकारी देने का आश्वासन दिया जहाँ CRPF के कैंप हैं और जहाँ security measures को देखते हुए ATMs/ Banking Outlets की व्यवस्था करना ज्यादा सुविधाजनक होगा	IG, operations के कार्यालय के द्वारा प्रदत्त 140 centres के list को SLBC द्वारा सभी LDMs को उपलब्ध कराकर उनसे वैसे सभी centres को visit कर यह बताने को कहा गया था कि यदि उन locations के पास कोई बैंक की शाखा अथवा ATM नहीं है तो वहां बैंको को चिन्हित कर उनका नाम SLBC को प्रेषित किया जाये ताकि उन जगहों पर चिन्हित बैंको को एटीएम खोलने के लिए कहा जा सके अब तक केवल तीन LDMs-जामतारा, खुंटी एवं गुमला , के द्वारा यह exercise किया गया है चूँकि कई बैंको ने ATM लगाये जाने पर अपनी सहमति दी है अतः LDMs से आग्रह है कि इस exercise को वे अबिलम्ब पूरा करें
18	ATR	ATR प्रेषित नहीं करने वाले बैंको के प्रधान कार्यालय को इस सम्बन्ध में SLBC द्वारा पत्र लिखा जाना	सभी बैंको द्वारा ATR संप्रेषित कर दिया गया है , परन्तु ATR का जबाब ज्यादा सतही ही प्रतीत होता है बैंको एवं LDMs से अनुरोध है कि ATR के reply को facts & figures के साथ substantiate किया जाये
19	PMFBY	सभी बैंको से सभी loanee farmers को insurance coverage दिये जाने और उससे संबंधित रिपोर्टिंग पोर्टल पर विधिवत तरीके से किये जाने का अनुरोध किया गया कृषि निदेशक, झारखण्ड सरकार ने सभी बैंको से prompt repayment के cases में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली interest subsidy का claim State Co-operative Bank (Nodal Agency) से अविलम्ब कर लिए जाने की अपील की	बैंको द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार खरीफ की फसल के लिए सभी 334911 eligible loanee farmers का insurance coverage PMFBY के तहत कर लिया गया है रिपोर्ट से परिलक्षित होता है कि सभी loanee एवं non loanee farmers , जिनका insurance coverage किया गया है, उनका आंकड़ा portal पर upload नहीं किया गया है चूँकि किसी प्रकार का नुकसान होने पर व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है, अतः सम्बंधित बैंको से आग्रह है कि इस कार्य को अविलम्ब पूरा कर लें
20	अगली SLBC की बैठक का महत्वपूर्ण agenda	कृषि क्षेत्र में बैंको के द्वारा अपेक्षाकृत संतोषप्रद प्रदर्शन नहीं होने के कारण और विकास आयुक्त द्वारा अगली SLBC के लिए agr credit growth पर prime focus दिए जाने सम्बन्धी निर्देश के आलोक में SLBC द्वारा सभा को बताया गया कि जल्द ही NABARD के तत्वाधान में सभी सम्बंधित हितधारकों के साथ बैठक कर इस दिशा में अपेक्षित प्रगति के लिए ठोस उपाय किये जायेंगे	SLBC की Agr Sub committee की बैठक NABARD द्वारा दिनांक 28.09.2018 एवं पुनः दिनांक 26.11.2018 को करायी गयी हालाँकि SLBC द्वारा इस सम्बन्ध में सभी बैंको एवं LDMs को दिनांक 30.08.2018 को ही कृषि क्षेत्र में ACP का कम से कम 50% उपलब्धि करने के लिए कहा गया और बार बार इस पर focus देने के लिए remind किया गया परन्तु इस दिशा में समुचित परिणाम अब तक नहीं आ पाया है

21	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	सभी बैंको से PMMY के तहत DFS द्वारा दिए गए बजट को district wise allocate कर SLBC को प्रेषित करने का आग्रह किया गया। श्री मदनेश मिश्रा ने मुद्रा योजना के तहत दिए गए नए ऋण का अलग से और साथ ही साथ ऋण प्राप्त लाभार्थियों द्वारा generate किये गए employees की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा	जिलावार मुद्रा ऋण का target बैंको द्वारा दे दिया गया है, परन्तु employment generation की सूचना किसी भी बैंक के द्वारा SLBC को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
22	PMAY	शहरी विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी बैंको से जून 2015 के बाद स्वीकृत वैसे Housing Loans जो PMAY की पात्रता रखते हैं उन्हें PMAY स्कीम में लाकर उसमें मिलने वाली subsidy की राशि claim कर लिए जाने की बात दोहरायी गयी। इसके साथ ही PMAY के लिए इच्छुक 16000 लाभार्थियों से contact करने का आग्रह किया गया जिनके details बैंको को भेजे गए हैं ताकि PMAY ऋण स्वीकृति की स्थिति में अपेक्षित गति लायी जा सके।	शहरी विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में बैंको को कोई आवेदन प्रेषित नहीं किया गया है पर पूर्व में प्रेषित लंबित आवेदनों में से लगभग 55 ऋण स्वीकृत किये गए हैं। अब तक बैंको को प्रेषित कुल 1876 आवेदनों में से 314 आवेदन स्वीकृत किये गए हैं।
23	उपसमिति	SBI से आग्रह किया गया कि सुरक्षा और आवास पर बनी उपसमिति की बैठक अविलम्ब करायी जाये। साथ ही NABARD से agr उपसमिति की बैठक जल्द से जल्द करने का अनुरोध किया गया।	इन दोनों उपसमितियों की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है॥
24	DCC/DLRC meeting	गढ़वा, पलामू, लातेहार और साहिबगंज के LDMs से जून quarter का DCC/DLRC meeting अविलम्ब कराये जाने का अनुरोध किया गया।	सभी सम्बंधित LDMs द्वारा जून quarter की बैठक कर ली गयी है।